

अपनी बात श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' के साथ



एक संक्षिप्त परिचय

- 2004-2009: सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा (दो कार्यकाल)
- 2009: झाँसी-ललितपुर संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित
- वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री, भारत सरकार

अपनाबुंदेलखंड डॉट कॉम की छोटी किन्तु उपलब्धियों भरी यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय तब जुड़ गया जब 24 जून, 2010 को वर्तमान केंद्रीय सरकार में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' ने इसके कार्यालय में आकर संगठन के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रस्तुत हैं श्री प्रदीप जैन और अपनाबुंदेलखंड डॉट कॉम के उप-संपादक अनुभव श्रीवास्तव के मध्य हुई बातचीत के कुछ अंश:

अ.श्री.: आपका आगमन हमारे लिए गौरव की विषय है और अपनाबुंदेलखंड डॉट कॉम समूह की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

प्र.जै.: जी धन्यवाद।

अ.श्री.: आप भारत की स्वतंत्रता के बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम और सबसे युवा सदस्य हैं। यह महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपे जाने पर आप कैसा महसूस करते हैं?

प्र.जै.: ये निस्संदेह एक चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व है। हमारे नेता माननीय श्री राहुल गाँधी जी ने मुझ पर अत्यंत विश्वास के साथ ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। मेरी भूमिका इसलिए और भी अहम् हो जाती है क्योंकि बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ हूँ जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीविका से सीधे तौर पर संबद्ध है। इसलिए बुंदेलखंड की आम जनता और विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुझसे काफी अपेक्षाएं हैं।

अ.श्री.: आपको अपने वर्तमान कार्यभार में कौन सी बड़ी चुनौतियाँ नज़र आती हैं?

प्र.जै.: ग्रामीण विकास मंत्रालय में मेरे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) को कारगर रूप से क्रियान्वित कराना है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है और भारत के वर्तमान ग्रामीण परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। यद्यपि इसमें हमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और अक्षमता की शिकायतें मिली हैं जिन पर राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से काबू पाया जाना नितांत आवश्यक है। ये हम सभी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और वर्तमान केंद्रीय सरकार सभी संबंधित मुद्दों का हल निकालने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है।

अ.श्री.: इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या योजना है?

प्र.जै.: ज़रूरत इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्र लोगों के बीच में मनरेगा और इसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। मनरेगा कोई आम सरकारी योजना नहीं बल्कि संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम है जिसके क्रियान्वन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की बनती है। लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि एक साल में सरकार से 100 दिन काम माँगना उनका कानूनी अधिकार है। इसके अलावा मनरेगा के प्रभावी रूप से क्रियान्वन और निगरानी के लिए नागरिक संगठनों की अधिक से अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आर० टी० आई० फाउंडेशन जैसे संगठन इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि सूचना का अधिकार आम लोगों के हाथ में व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सबसे कारगर हथियार है।

अ.श्री.: मनरेगा में व्याप्त अक्षमता और भ्रष्टाचार के अलावा बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में आपके विचार से कौन-कौन से समस्या-बिंदु हैं?

प्र.जै.: निरक्षरता, सूखा, गरीबी और बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड के लोगों का बाहर पलायन बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर तात्कालिक रूप से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। ये सारी समस्याएं क्षेत्र में विकास के अभाव के कारण उत्पन्न हुई हैं। श्री राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड के कई दौरें किया और वहां के हालात देखकर चिंतित हुए। तदनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि संबंधी समस्याओं के निदान हेतु सामरा कमेटी नियुक्त की गई जिसकी अनुशंसाओं के अनुसार क्षेत्र के लिए 7266 करोड़ रुपये के बुंदेलखंड पैकेज की घोषणा की गई जिसका संचालन केंद्रीय सरकार, योजना आयोग के माध्यम से कर रही है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भी वहां की स्थिति को अपने संज्ञान में लिया है। हम लोग वहां की स्थिति से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना बना रहे हैं।

अ.श्री.: आपके विचार में अप्रवासी बुंदेलखंडी समुदाय, जो देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुका है, किस प्रकार क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है?

प्र.जै.: अगर बुंदेलखंड को अपनी वर्तमान स्थिति से उबरना है तो बुंदेलखंड क्षेत्र के बाहर के समूह का सहयोग अति-महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड की "शौर्य, तपस्या, त्याग और बलिदान" की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्हें आगे आकर क्षेत्र के विकास के लिए न केवल अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए अपितु बुंदेलखंड में रोज़गार उत्पन्न करने और उसे विकास-उन्मुख बनाने हेतु पूंजी-निवेश करने के लिए भी आगे आना चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी का एक आदर्श प्रतिमान स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

अ.श्री.: अंत में, मैं आपसे हमारी वेबसाइट अपनाबुंदेलखंड डॉट कॉम के द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा?

प्र.जै.: ये एक उत्कृष्ट पहल है जिसके लिए मैं अपनाबुंदेलखंड डॉट कॉम समूह के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। इसमें दी गई सारगर्भित और उपयोगी जानकारियाँ न केवल क्षेत्र के आम लोगों, बल्कि सरकार और प्रशासन में उच्चतम स्तरों पर विराजमान लोगों के भी बीच में बुंदेलखंड की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। मेरी सभी से अपील है कि क्षेत्र, जाति, धर्म और समाज के बन्धनों से ऊपर उठकर इस मंच के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करने के लिए आगे आर्यें। मैं अपनाबुंदेलखंड डॉट कॉम समूह के सदस्यों को उनके प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।